

रजिस्ट्री सं. डी-222

REGISTERED No. D-222



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

भ. 14]

नई दिल्ली, रानिवार, अप्रैल 5, 1969 (चैत्र 15, 1891)

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 5, 1969 (CHAITRA 15, 1891)

इस भाग में विश्व पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अस्तग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखा भारत का असाधारण राजपत्र 10 मार्च 1969 तक प्रकाशित किया गया है :—

The undermentioned *Gazette of India Extraordinary* was published up to the 10th March 1969 :—

१५

संख्या और तारीख

No. and Date

द्वारा जारी किया गया

Issued by

विषय

Subject

TC(PN)/69,  
3-69

Min. of Foreign Trade  
& Supply

Import Policy for Registered  
Exporters for the year  
April 1968—March 1969

## विषय-सूची (CONTENTS)

भाग I—खंड 1—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 301	भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	पृष्ठ 1211
भाग I—खंड 2—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	383	भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई <sup>1</sup> विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	11
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई <sup>1</sup> विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	297	भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	323
भाग I—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—	भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	123
भाग II—खंड 1—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	45
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	207
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) .. .. ..	945	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	61
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. ..	Page 301	पूरक संख्या 14— 28 मार्च 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट 8 मार्च 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बिमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	553
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appoint- ments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. ..	383	PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii) —Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities ( <sup>2</sup> than the Administrations of Un Territories) .. .. ..	
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. ..	11	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules notified by the Ministry of D	
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appoint- ments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence .. .. ..	297	PART III—SECTION 1.—Notification Auditor General, Uni Commission, Railw High Courts and t ordinate Offices of India ..	
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. ..	—	PART III—SECTION 2 issued by	
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. ..	—	PART III—SECTI und sic	

## भाग I—खण्ड 1

## PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम् व्यावालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेदों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

**Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court**

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 5 अप्रैल 1969

## नियम

सं० 5/22/69-के० से० (I)—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की प्रवर सूची में नाम शामिल करने के लिए दिसम्बर, 1969 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं।

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रवर सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग द्वारा प्रकाशित नोटिस में किया जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नलिखित में उल्लिखित किसी जाति/आदिम जाति से है—अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (मंशोधन) अधिनियम 1956 के साथ पठित अनुसूचित जाति/आदिम जाति सूचियां (आणोधन) आदेश 1956, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956 संविधान (अंडमान और निकोद्वारा द्वारा समृद्ध) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (शादग और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 तथा संविधान (अनुसूचित आदिम जातियों) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिणाम में विवित विधि से किया जाएगा।

परीक्षा की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

4. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड के या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II के स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी, जो 1 जुलाई 1969 को नियमित लिखित शर्त पूरी करते हैं, इस परीक्षा में बैठ सकेंगे:—

(1) सेवा-काल—उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसने नियमित पदों में से किसी एक या अधिक पद पर यथास्थिति कम-से-कम पांच वर्ष तक लगातार सेवा की हो:—

- (i) सहायक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा)।
- (ii) आशुलिपिक (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा) ग्रेड II।
- (iii) आशुलिपिक (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा) ग्रेड III।
- (iv) केन्द्रीय सरकार या किसी गज्ज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद जो यदि 1 जुलाई 1959 के पहले ग्रहण किया गया हो तो उसका वेतनमान कम-से-कम 160 रु० और अधिक-से-अधिक 450 रुपये होना चाहिए और यदि वह 1 जुलाई 1959 को या उसके बाद ग्रहण किया गया हो तो उसका वेतन-मान कम-से-कम 210 रु० और अधिक-से-अधिक 530 रु० होना चाहिए।

टिप्पणी : केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड के या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II के स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी, जो 26 अक्टूबर 1962 को आपात काल घोषित होने पर उस अवधि में, अर्थात् 26 अक्टूबर 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक, गशस्त्र मेना में भर्ती हुआ हो, गशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तित होने पर, गशस्त्र सेना में की गई सेवा की अवधि (प्रणिक्षण की अवधि समेत, यदि कोई हो), को निर्धारित कम-से-कम सेवा में मिलाने की अनुमति दी जाएगी।

(2) (क) आयु : उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी उसका जन्म 1 जुलाई 1929 से पहले न हुआ हो, लेकिन शर्त यह है कि :—

- (i) कोई भी उम्मीदवार जिसका जन्म 1 जुलाई 1929 से पहले हुआ हो लेकिन 1 जुलाई 1928 से पहले न हुआ हो तथा जिसकी 1 जुलाई, 1968 को 5 वर्ष से कम की लगातार सेवा न हो, और
- (ii) कोई भी उम्मीदवार जिसका जन्म 1 जुलाई 1928 से पहले हुआ हो लेकिन 1 जुलाई 1927 से पहले न हुआ

हो तथा जिसकी 1 जुलाई 1967 को 5 वर्ष से कम की लगातार सेवा न हो, वह उपर्युक्त नियम 4 (1) में उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक पदों के लिए यथास्थिति इस परीक्षा में बैठने के लिए विशेष मामले के रूप में पात्र होगा । यह छूट केवल 1969 में होने वाली परीक्षा के लिए ही दी जायेगी ।

**टिप्पणी :** 40 वर्ष की आयु सीमा केवल इस परीक्षा और उत्तरवर्ती दो परीक्षाओं पर ही लागू होगा ।

(ख) उपर्युक्त निर्धारित आयु-सीमा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड के या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II में स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी, जो 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल धोषित होने पर, उस अवधि में अर्थात् 26 अक्टूबर 1962 से 9 जनवरी 1968 तक सशस्त्र सेना में भर्ती हुआ हो और जो वहां से प्रत्यावर्तित हो गया हो, उसके लिए सशस्त्र सेना में की गई सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि समेत यदि कोई हो) की छूट होगी ।

(ग) ऊपर बताई गई ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित रूप में और भी छूट दी जायेगी :—

- (i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तो अधिक-से-अधिक 5 वर्ष तक;
- (ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी 1964 या उसके बाद प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;
- (iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी 1964 या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक-से-अधिक 8 वर्ष तक;
- (iv) यदि उम्मीदवार संघराज्य-क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक-से-अधिक 5 वर्ष तक;
- (v) यदि उम्मीदवार लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद में लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;
- (vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और अक्टूबर 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष तक;
- (vii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व

टांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजित हो तो अधिक-से-अधिक 3 वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और 1 जून 1963 का या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष तक;

(x) किसी दूसरे देश से ज्ञागड़ों के दौरान अथवा किसी उपद्रव-ग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाईयों के समय अणवत हुए तथा उसके परिणाम स्वरूप नौकरी निर्मुक्त रक्षा-सेवा-कार्मिकों के लिए अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रव-ग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के समय अणवत हुए तथा उसके परिणाम स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा-सेवा-कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हो, अधिक-से-अधिक 8 वर्ष तक और

(xii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य-क्षेत्र गोवा, दमन और दिव का निवासी हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक ।

**ऊपर बताई गई स्थितियों को छोड़ कर और किसी भी हालत में निर्धारित आयु-सीमाओं में छूट नहीं दी जा सकती ।**

**ध्यान बें :—**

1. संधर्म प्राधिकारी के अनुमोदन से निःसंवर्ग पदों (एक्स काउर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्त किए गए सहायक/आशुलिपिक इस परीक्षा में बैठ सकेंगे, यदि वे अन्य सभा प्रकार से इसके पात्र हों ।

फिर भी यह बात उस सहायक/आशुलिपिक के लिए लागू नहीं होती जो दूसरे निःसंवर्ग पद या सेवा में “स्थानान्तरण” द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और सहायक/आशुलिपिक वर्ग में उसका ग्रहण-धिकार कुछ समय के लिए बना हो ।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के जिन सहायकों ने और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के जिन आशुलिपिकों ने भारतीय विदेश सेवा (बी) में नियुक्ति के लिए अपना विकल्प दिया हो और जो ऐसे विकल्प के आधार पर उस सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त किए जा चुके हों, उन्हें इस परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा ।

3. जिस अनुसूचित जाति के सहायक को 14 अप्रैल, 1952 से 30 अप्रैल 1954 की अवधि में पदोन्नति की समझी गई तारीख का लाभ देकर उसकी तदर्थि पदोन्नति की गई हो, उसके मामले में उपर्युक्त नियम के प्रयोगन के लिए सहायक ग्रेड में उसके सेवा काल का हिसाब उसे सहायक के रूप में पदोन्नत करने की वास्तविक तारीख को ध्यान में रखते हुए, लगाया जाएगा ।

4. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पावता या अपावता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

5. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सटिफीकेट आफ एडमीशन) नहीं होगा ।

6. यदि कोई उम्मीदवार इस बात का दोषी हो या आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें कोई हेरा-फेरी की गई है या उसमें कोई ऐसी बात लिखी है जो गलत या कूटी है या उसमें कोई तथ्य छिपाया गया है या उसने परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अनियमित या अनुचित उत्ताप अपनाया है अथवा उसने परीक्षा भवन में कोई अनियमित तरीका अपनाया है या अपनाने की चेष्टा की है अथवा उसने परीक्षा-भवन में कोई अनुचित आचरण किया है तो उस पर दाण्डक अभियोग चलाया जा सकता है और साथ ही—

(क) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव के लिए ली जाने वाली परीक्षा या साक्षात्कार (इन्टरव्यू) में शामिल होने से स्थायी रूप से या किसी निश्चित अवधि के लिए वंचित किया जा सकता है ।

(ख) समुचित नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

7. यदि कोई उम्मीदवार किसी और प्रकार से अपने उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दे दिया जाएगा ।

8. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के परिशिष्ट में निर्धारित शुल्क देना होगा ।

9. परीक्षा के बाद आयोग हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीदवारों के नाम अपेक्षित संख्या तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा, जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गये हों ।

लेकिन गर्त यह है कि आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार योग्य सिद्ध न हो प्रशासनिक कुशलता को ध्यान में रखते हुए उस सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दे तो उसकी उस सेवा में यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आयोग सिफारिश करेगा ।

**टिप्पणी :** उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता-परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा (क्वालीफाइंग एक्जेमिनेशन) । इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुभाग अधिकारी ग्रेड की प्रवर सूची में किसने उम्मीदवारों के नाम शामिल

किए जायें इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है । इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया ही जाय ।

10. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

11. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने मात्र से ही चुनाव का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चुनाव के लिए हर प्रकार से पात्र और उपयुक्त है ।

परन्तु आयोग ने जिस उम्मीदवार के चुनाव के लिए सिफारिश की है उसे चुनाव के लिए अपात ठहराते समय आयोग से परामर्श लेना आवश्यक होगा ।

12. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अपने पद से त्याग पत्र देंगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना या जिसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हों या जो किसी निःसंबंधीय पद या दूसरी सेवा में “स्थानान्तरण” द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो चाहे वह सहायक/आशुलिपिक वर्ग, यथास्थिति में कुछ समय के लिए ग्रहण-धिकार रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

तथापि, वह उस सहायक/आशुलिपिक पर लागू नहीं होता, जो सक्षक प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंबंधीय पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो ।

13. उम्मीदवारों की वरिष्ठता, जो 26 अक्टूबर, 1962 को आपात स्थिति घोषित होने पर, उस अवधि में अर्थात् 26 अक्टूबर 1962 से 9 जनवरी 1968 तक सशस्त्र सेना में भर्ती हुए और जो अपने सशस्त्र सेना की सेवा में अनुभाग अधिकारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता-परीक्षा (परीक्षायों) में न बैठ सके, उन्हें इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुभाग अधिकारी ग्रेड की प्रवर सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए अन्तिम सिफारिश होने पर भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये विशेष आदेशों के अनुसार विनियमित की जायेगी ।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

### परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

**भाग I—**नीचे पैरा 2 में बताए गए विषयों की कुल 450 अंकों की सिखित परीक्षा ।

**भाग II—**आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार उम्मीदवारों के सेवा वृत्तों (रेकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन, जिसके लिए अधिकतम अंक 130 होंगे ।

2. भाग 1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए दिया जाने वाला समय और उसके अधिकतम अंक इस प्रकार होंगे :—

विषय	अधिकतम अंक	दिया जाने वाला समय
(1) टिप्पणी, मसौदा और सार लेखन . . . .	100	2½ घंटे
(2) भारत सरकार के सचिवालय और संबंध कार्यालयों में अपनाई जाने वाली कार्यविधि और कार्य प्रणाली . . . .	100	2½ घंटे
(3) भारत के संविधान और शासन-तंत्र का सामान्य ज्ञान, संसदीय पद्धति और कार्यविधि . . . .	100	2½ घंटे
(4) सामान्य वित्तीय और सेवा-नियमावली (जनरल फाइनेन्शियल एण्ड सर्विस रूल्स)	50	1½ घंटे
(5) सामान्य ज्ञान . . . .	100	2½ घंटे

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण संलग्न अनुसूची में दिये अनुसार होगा। जहां नियमों, आदेशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है वहां उम्मीदवारों को इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए जाने वाले संशोधन की जानकारी रखने की अपेक्षा की जायेगी।

4. सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखने होंगे।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (बवालीफाइंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है।

7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिये जायेंगे।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक काट लिए जायेंगे।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भावाभिव्यक्ति कम-से-कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

### अनुसूची

#### परीक्षा का पाठ्य-विवरण

1. टिप्पणी, मसौदा और सार-लेखन।

विशिष्ट समस्याओं पर टिप्पणियां और मसौदे तैयार करने के अतिरिक्त उम्मीदवारों को संक्षेप या सार लिखने के लिए अवतरण भी दिये जा सकते हैं।

2. भारत सरकार के सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में अपनाई जाने वाली कार्यविधि और कार्य प्रणाली।

इसका उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में अपनाई जाने वाली पद्धतियों और कार्यविधि के विषय में गहन और विस्तृत परीक्षा लेना है। इस विषय में तीव्र दी जा रही पुस्तकों से कुछ संदर्शन प्राप्त हो सकता है :—

(i) "मैन्युअल आफ आफिस प्रोसीजर" जो अधिसूचना के समय लागू हो।

(ii) सचिवालय प्रणिक्षण स्कूल द्वारा प्रकाशित "नोट्स आन आफिस प्रोसीजर" का अध्याय 7 और

(iii) मंत्रिमंडल के समक्ष, प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी किए गए अनुदेश।

3. भारत के संविधान और शासन-तंत्र का सामान्य ज्ञान; संसदीय पद्धति और कार्यविधि।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को निम्नलिखित का ज्ञान होना चाहिए :—

(i) भारत के संविधान के मुख्य-मुख्य सिद्धांत,

(ii) लोक सभा और राज्य सभा की कार्यविधि और कार्यसंचालन नियमावली और

(iii) भारत के शासन-तंत्र का संगठन-मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के पद्धतियों का निर्धारण और उनके विषयों का बंटवारा तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध।

4. सामान्य वित्तीय और सेवा नियमावली 1 इसके लिए निम्नलिखित पुस्तकों का अध्ययन किया जा सकता है :—

(i) फण्डमेण्टल एण्ड स्प्लीमेण्टरी रूल्स (महालेखापाल, डाक-तार का संकलन)।

(ii) सी० एस० आर० (केवल पेंशन सम्बन्धी अंश)।

(iii) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 [दि सेप्ट्रल सिविल सर्विसेज (कांडकट) रूल्स 1964]

(iv) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 [दि सेप्ट्रल सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स 1965]।

(v) सामान्य वित्तीय नियम (जनरल फाइनेन्शियल रूल्स) (रिवाइज़ड एण्ड एन्टार्ज़ेंड) 1963।

(vi) कम्पाइलेशन आफ दि डलीगेशन आफ फाइनेन्शियल पार्वस रूल्स, 1958 (विद गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया डिसीजन्स) एण्ड डेलीगेशन आर्डस, डेटेड दि 1 जून 1962।

5. सामान्य ज्ञान

इन प्रश्न-पत्र में तात्कालिक महत्व के विषयों पर प्रश्न पुछे जाएंगे। पंच वर्षीय योजनाओं और सामुदायिक विकास योजनाओं

की सामान्य और मुख्य बातों के सम्बन्ध में उम्मीदवारों के ज्ञान की परीक्षा की जाएगी और यह जानने के लिए प्रश्न पूछे जायेंगे कि उम्मीदवारों को वर्तमान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की वृद्धि-मत्तापूर्ण जानकारी है या नहीं, जो किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारों के उत्तरों से उनके पाठ्य-पुस्तकों, रिपोर्ट आदि के ज्ञान की बजाए यह पता चलना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को भली भांति समझ कर बुद्धिमानी से उत्तर दिये हैं।

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च, 1969

### प्रस्ताव

सं० 27/23/68-कोआई—भारत सरकार ने, अपने 2 अप्रैल, 1968 के प्रस्ताव सं० 27/5/67-कोआई के अनुसार, सीमांशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन किया था। भारत सरकार ने अब निण्य किया है कि परिषद् का कार्य अधिक अच्छे ढंग से चलाने के लिये मंत्री, राजरब तथा व्यय एवं उप-वित्त-मंत्री को परिषद् के काम-काज से सम्बन्धित होना चाहिये और एतदनुसार उनको उक्त परिषद् के उपाध्यक्ष-पदों पर नियुक्त किया जाता है।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव को सर्वमाधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

डी० पी० आनन्द, अतिरिक्त सचिव

### खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

### शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली-1, दिनांक 25 फरवरी 1969

सं० 2-4/69-फेम—भारत सरकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प सं० 2-2/65-फेम, दिनांक 14 दिसम्बर 1965 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि अब से खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) में या उसके अधीन कार्य करने वाले एक अधिकारी को समय-समय पर भूख से मुक्ति आन्दोलन की राष्ट्रीय अभियान समिति के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा अपने पूर्ण स्वविवेक से इस समिति के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जायेगा।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र की प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसद् कार्य विभाग, राष्ट्रपति के निजी व सेवा सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, भारत सरकार के महा परीक्षक एवं भूख सुचित आन्दोलन से संबंधित सभी संगठनों एवं व्यक्तियों को सूचित किया जाये।

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जावे।

जगदीश चन्द्र माथुर, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1969

### संस्ताव

सं० 2-15/68-पुनर्गठन (प्रशासन) — भारतीय राजपत्र के भाग I अनुभाग 1 में प्रकाशित, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के संस्ताव संख्या 2-34/65 रिआर्ग-सीसी दिनांक 30 मार्च, 1966 तथा 2-22/67 रिआर्ग (प्रशासन) दिनांक 11 सितम्बर, 1967 के सिलसिले में भारत सरकार ने निम्नलिखित अनुसंधान संस्थानों/संस्थाओं का, इनके क्षेत्रीय तथा उप-केन्द्रों/केन्द्रों शत्यादि सहित (किन्तु संस्थाओं के आगे उल्लिखित कार्यों को छोड़कर) प्रशासनिक नियंत्रण 1 अप्रैल, 1969 से भारतीय कृषि अनुसंधान संसाधनी को हस्तांतरित करने का निश्चय किया है।

- (1) भारतीय गत्ता अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
- (2) गत्ता प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर (तमिलनाडु)
- (3) अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्था, नई दिल्ली।

इन कार्यों के प्रतिरिक्षत— (क) मुख्यालय तथा प्रादेशिक केन्द्रों के हवाई फोटो व्याख्या एकक, तथा

(ख) प्रादेशिक केन्द्रों के चार सहायक भू-सर्वेक्षण अधिकारियों तथा मुख्यालय के एक सहायक भू-सर्वेक्षण अधिकारी के पर्यावरण कर्मचारियों के माथ भू-सर्वेक्षण करने वाली सबह फील्ड पार्टियां।

2. भारत सरकार ने उपरिलिखित परा 1 में दिये गये संस्थानों/संस्थानों की, सरकार द्वारा निश्चित की गई, चल व अचल सम्पत्ति, दावे, व्यवहार्य दावे, ऋण तथा दायित्वों सहित परि-सम्पत्तियां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को कालान्तर में निपादन किये जाने वाले हस्तान्तरण के औपचारिक विसेख अथवा विलेखों द्वारा हस्तांतरित करने का भी निश्चय किया है।

3. उपरिलिखित पैग 1 में उल्लिखित संस्थानों/संस्था की कार्य विधियों की वित्तीय व्यवस्था वे लिए भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को प्रति वर्ष आवश्यक वार्षिक सहायक अनुदान देगी।

### आदेश

आदेश है कि इस संस्ताव की एक-एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ प्रशासनित प्रदेशों तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाये।

2. यह भी आदेश है कि यह संस्ताव जन साधारण की सूचना वे लिए भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

भ० रा० पटेल, सचिव

### सिचाई व विजली मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 1969

#### संकल्प

सं० ब्रि० दो-१(7)/६५—इस मंत्रालय के संकल्प सं० ई० एल० २-१(7)/६५, दिनांक १२ फरवरी, १९६८ में, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय विजली सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है, “संसद् सदस्य” शीर्ष के नीचे वर्तमान प्रविष्टि सं० ७ के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि कर दी जाएः—

“७. श्री जी० वाई० कृष्णन, संसदसदस्य (लौक सभा)”

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प सम्बन्धित संसदस्यों, राज्य सरकारों, राज्य विजली बोर्डों, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक व महा-लेखा परीक्षक के पास भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

दिनांक मार्च 1969

सं० ई० एल० २-१२(२१)/६१-जिल्द-III—दिल्ली में तीन सेटों के प्रतिष्ठापन के लिए जिन में से प्रत्येक की क्षमता ५०/६२.५ मैगावाट होगी, दिल्ली ताप परियोजना नियन्त्रण बोर्ड के गठन से सम्बन्धित इस मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या ई० ई० एल०-II-१२(२१)/६१ दिनांक २६ सितम्बर, १९६२ में पैरा २ की वर्तमान प्रविष्टि (३) और पैरा ६ की वर्तमान प्रविष्टि xi के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां कर दी जाएः—

#### पैरा २

(१३) सचिव (स्थानीय स्वायत्त सरकार और जन कार्य विभाग) दिल्ली प्रशासन . . . . . सदस्य

#### पैरा ६

(xi) सचिव (स्थानीय स्वायत्त सरकार तथा जन कार्य विभाग) दिल्ली प्रशासन . . . . . सदस्य

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को पंजाब और हरियाणा की सरकारों, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, हरियाणा विजली

बोर्ड, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत सरकार के महानियन्त्रक तथा लेखा परीक्षक के पास भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

के० पी० मश्हानी, सचिव

#### संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 1969

सं० २२/७/६६-वि०का० एक—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या २२/७/६६-वि०का० एक, दिनांक १० दिसम्बर, १९६८ की कण्डका २ में ‘मुख्य मुत्रियों की समिति’ के नीचे क्रम संख्या २ वे आये वर्तमान प्रविष्टि की बजाय निम्नलिखित प्रविष्टि कर दी जाए।

“२, मुख्य मंत्री, पंजाब या उसका प्रतिनिधि”:

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को पंजाब, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों और वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रोलय, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय और योजना आयोग को सूचनार्थ प्रेषित कर दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और संबंधित राज्य सरकारों से कहा जाए कि वे भी आम सूचना के लिए राज्य के गाजपत्रों में इसे प्रकाशित कर दें।

ओ० पी० चड्ढा, उप-सचिव

#### सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-१, दिनांक 20 मार्च 1969

सं० २४/३/६८-एफ० पी०—समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या १/२४/५८-एफ० पी०, तारीख ५ फरवरी, १९५९ के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अम्बर्ह सलाहकार मंडल के सदस्य श्री एच० आर० महाजनी को श्री ललित कुमार खटाऊ के स्थान पर अगले आदेश तक फिल्म सलाहकार बोर्ड, अम्बर्ह का सदस्य नियुक्त किया है।

2. केन्द्रीय सरकार ने श्री जी० एस० पोदार के स्थान पर डा० डी० के रेंगनेकर को भी दो वर्ष के लिये फिल्म सलाहकार बोर्ड अम्बर्ह का सदस्य नियुक्त किया है।

वसू राम अग्रवाल, अवर सचिव

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 26th March 1969

SUBJECT : Long Vacation, 1969

No. F. 44/69-SCA(G).—In pursuance of Rule 4 of Order II of the Supreme Court Rules, 1966, the Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to direct that the Supreme Court will be closed for the Annual Summer Vacation from Monday, the 5th May, 1969 to Sunday, the 13th July, 1969 (both days inclusive) and will re-open on Monday, the 14th July, 1969.

The Hon'ble the Chief Justice of India has also been pleased under Rule 6, Order II of the aforesaid Rules to appoint the Hon'ble Mr. Justice S. M. Sikri and the Hon'ble Mr. Justice G. K. Mitter to be Vacation Judges to hear matters of an urgent nature, which under these Rules may be heard by a Judge sitting singly, for the respective periods shown against their names below :—

The Hon'ble Mr. Justice S. M. Sikri from 5th May to 8th June, 1969 (both days inclusive).

The Hon'ble Mr. Justice G. K. Mitter from 9th June to 13th July, 1969 (both days inclusive).

The Hon'ble Mr. Justice S. M. Sikri will sit on Tuesdays the 20th May and 3rd June, 1969. The Hon'ble Mr. Justice G. K. Mitter will sit on Tuesdays the 17th June and 1st July, 1969. Sittings will, however, continue on the next succeeding days if matters fixed for any day are not finished on that day.

Except on Saturdays and holidays, the offices of the Court shall be open during vacation between 8 a.m. and 12.30 p.m. daily; but on the days notified for the vacation sittings the hours shall be 10 a.m. to 4 p.m.

No plaints, appeals, petitions or other documents except those which require to be immediately or promptly dealt with, will be filed or received in the Registry of the Court during the period the Court is in Vacation.

The Registry will open for filing purposes from Monday, the 14th July, 1969, but as from the 7th July, 1969, for convenience of parties, the office of the Court will receive during the working hours all plaints, appeals, petitions or other documents which may be ready for filing with the parties.

Y. D. DESAI, Registrar

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## RULES

New Delhi, the 5th April 1969

No. F. 5/22/69-CS(1).—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service to be held by the Union Public Service Commission in December, 1969 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select list will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service or of Grade II of the Central Secretariat Stenographers Service, who on the 1st July 1969, satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination :—

(1) *Length of Service* :—He should have rendered a continuous service of not less than five years in any one or, as the case may be more than one, of the following posts, namely :—

(i) Assistant (C.S.S.)

(ii) Stenographer (C.S.S.S.), Grade II.

(iii) Stenographer (C.S.S.S.), Grade III.

(iv) any other post, under the Central Government or a State Government, the minimum and the maximum of the scale of pay of which were not less than rupees 160 and rupees 450 respectively in the case of a post held prior to 1st July 1959 and rupees 210 and rupees 530 respectively in the case of a post held on or after 1st July 1959.

*NOTE.*—Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service or of Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962, to 9th January, 1968, would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

(2) (a) *Age* :—He should not be more than 40 years of age i.e. he must not have been born earlier than 1st July, 1929;

Provided that

(i) any candidate born earlier than 1st July, 1929, but not earlier than 1st July 1928, who had rendered a continuous service of not less than five years on 1st July, 1968, and

(ii) any candidate born earlier than 1st July, 1928, but not earlier than 1st July 1927, who had rendered a continuous service of not less than five years on 1st July, 1967,

in any one or as the case may be, more than one, of the posts mentioned in Rule 4(1) above, shall also be eligible for admission to this examination as a special case. This relaxation would be admissible for the examination to be held in 1969 only.

*NOTE.*—The age limit of 40 years will apply to this examination and to the next two subsequent examinations only.

(b) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a permanent or regularly appointed temporary officer of the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service or Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962, to 9th January, 1968, and who has reverted therefrom, to the extent of the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces.

(c) The age limit prescribed above will be further relaxable :

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced persons from East Pakistan and has migrated to India on or India on or after 1st January, 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondi-

cherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years, if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PREScribed CAN IN NO CASE BE RELAXED.

NOTE 1.—Assistants/Stenographers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This, however, does not apply to an Assistant/Stenographer who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer", even if he continues to have a lien in the Assistants/Stenographer's Grade, as the case may be, for the time being.

NOTE 2.—Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who have opted for appointment to the I.F.S. (B) and have been appointed to any grade of that Service in pursuance of such option shall not be eligible for admission to the examination.

NOTE 3.—In the case of a Scheduled Caste Assistant given *ad hoc* promotion with the benefit of "deemed" date of promotion during the period 14th April, 1952 to the 30th April, 1954, his actual date of promotion as Assistant will be taken into consideration for computing the length of service in the Assistants' Grade for the purpose of the above rule.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the

examination hall may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution:—

(a) be debarred permanently or for a specified period by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

10. After the examination, candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of the Section Officers' Grade up to the required number.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission, is declared by them to be suitable for inclusion in the Select List for the Section Officers' Grade with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for inclusion therein up to the number reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Section Officers' Grade on the results of the examination, is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

13. A candidate, who, after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Service/Central Secretariat Stenographers' Service, or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department, or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' even if he continues to have a lien in the Assistants/Stenographers' Grade, as the case may be, for the time being, will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to an Assistant/Stenographer who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

14. The seniority of candidates who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962, to 9th January, 1968, and who could not compete at the Section Officers' Grade Limited Departmental Competitive Examination(s) held during the period of their service in the Armed Forces shall be regulated in accordance with the special orders issued by the Government of India in this behalf, in case they are finally recommended for inclusion in the Select List for the Section Officers' Grade on the results of this examination.

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

## APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I. Written examination carrying a maximum of 450 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II. Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion, carrying a maximum of 150 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the time allowed and the maximum marks allotted to each paper will be as follows :—

Subject	Maximum marks.	Time allowed
(1) Noting and Drafting, Precis-Writing	100	2½ hours
(2) Procedure and Practice in Government of India Secretariat and attached Offices. . . . .	100	2½ hours
(3) General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government; Practice and procedure in Parliament. . . . .	100	2½ hours
(4) General Financial and Service Rules.	50	1½ hours
(5) General Knowledge . . . . .	100	2½ hours

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached schedule.

Where knowledge of the Rules, orders, instructions, etc., is required candidates will be expected to be conversant with amendments issued up to the date of Notification of this examination.

4. All question papers must be answered in English.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

## SCHEDULE

## Syllabus of the Examination

## (1) Noting and Drafting, Precis Writing.

In addition to question requiring candidates to prepare Notes and Drafts on specified problems, passages may also be set for summary or precis.

## (2) Procedure and Practice in Government of India Secretariat and attached offices :—

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and Attached Offices. Some guidance on the subject can be obtained from—

- (i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification;
- (ii) Chapter 7 of "Notes on Office Procedure" issued by the Secretariat Training School; and
- (ii) Instructions issued by the Cabinet Secretariat regarding presentation of cases to the Cabinet.

(3) General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government; Practice and Procedure in Parliament.

NOTE : Knowledge of the following will be expected : (1) the main principles of the Constitution of India; (ii) Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha; and (iii) the organization of the machinery of the Government of India— designation and allocation of subjects between Ministries Departments, and Attached and Subordinate Offices and their relation *inter se*.

## (4) General Financial and Service Rules.

The following books are recommended :—

- (i) Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P. & Ts. compilation).
- (ii) C.S.R. (Pension portion only).
- (iii) The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.
- (iv) The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.
- (v) Compilation of the General Financial Rules (Revised and Enlarged) 1963.
- (vi) Compilation of the Delegation of Financial Power Rules, 1958 (with Government of India Decisions) and Delegation Orders, dated the 1st June, 1962.

## (5) General Knowledge.

The paper will cover subjects of interest and importance at the present day. Questions will be set to test knowledge of the broad and salient features of the Five Year Plans and Community Development Schemes, as also intelligent awareness of current affairs, both national and international which an educated person may be expected to have. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, reports etc.

**MINISTRY OF FINANCE**  
**Department of Revenue and Insurance**  
**RESOLUTION**

New Delhi, the 20th March 1969

No. 27/23/68-Coord.—The Government of India had reconstituted the Customs and Central Excise Advisory Council *vide* its Resolution No. 27/5/67-Coord., dated the 2nd April, 1968. The Government of India have now decided that for the better functioning of the Council the Minister of Revenue and Expenditure and the Deputy Minister of Finance should be associated with the working of the Council and accordingly appoints them as Vice-Chairman of the said Council.

## ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. P. ANAND, Additional Secy.

## Department of Economic Affairs

New Delhi, the 25th March 1969

No. F. 3(24)-BC/69.—It is hereby notified that, with effect from the 1st April, 1969, the Central Government work at Patna, will be taken over from the State Bank of India by the Patna Office of the Reserve Bank of India.

K. YESURATNAM, Under Secy.

## MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

## (Department of Agriculture)

New Delhi, the 25th February 1969

## CORRIGENDUM

No. 2-4/69-FAME.—In partial modification of the Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community

Development and Coopn. (Department of Agriculture) Resolution No. 2-2/65-FAME dated the 14-12-65 it is hereby notified that henceforth an officer working in or under the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coopn. (Department of Agriculture) will be appointed from time to time to act as Member-Secretary of the National Campaign Committee of Freedom From Hunger Campaign by the Executive President of the Committee in his sole discretion.

#### ORDER

ORDERED that a copy of this Corrigendum be communicated to all State Governments, Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Private and Military Secretary to the President, the President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, all Ministries of the Government of India, Planning Commission, the Auditor General of India and all organisations/individuals connected with the Freedom From Hunger Campaign.

ORDERED also that the Corrigendum be published in the Gazette of India.

J. C. MATHUR, Addl. Secy.

New Delhi, the 19th March 1969

#### RESOLUTION

No. 2-15/68-Reorgn. (Adm.)—In continuation of Resolutions Nos. 2-34/65-Reorgn. (CC), dated the 30th March, 1966 and 2-22/67-Reorgn. (Admn.), dated the 11th September, 1967 of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation—published in the Gazette of India, Part I, Section 1—the Government of India have further decided to transfer the administrative control of the following Research Institutes/Organisation, including their Regional and Sub-Stations/Centres etc., but excluding the items of work indicated against the Organisation, to the Indian Council of Agricultural Research Society with effect from 1st April, 1969:—

- (i) Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow (Uttar Pradesh).
- (ii) Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore (Tamil Nadu).
- (iii) All India Soil and Land Use Survey Organisation, New Delhi.

*Excluding*—(a) The Aerial Photo Interpretation Units both at the Headquarters and the Regional Centres, and

(b) Seventeen field parties for carrying out Soil Survey work with the supervisory staff of four Assistant Soil Survey Officers at Regional Centres and one Assistant Soil Survey Officer at Headquarters.

2. Government have also decided to transfer such movable and immovable property, assets including claims and actionable claims and debts and liabilities of the Institutes/Organisation mentioned in para 1 above to the Indian Council of Agricultural Research as may be decided by the Government by a formal deed or deeds of transfer to be executed later. The nature and the form of the deeds would be determined later.

3. The Government of India will give requisite annual grants-in-aid to the Indian Council of Agricultural Research for financing the activities of the Institutes/Organisation mentioned in paragraph 1 above.

#### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries and Departments of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. R. PATEL, Secy.

#### MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 17th March 1969

#### RESOLUTIONS

No. EL.II-1(7)/65.—The existing entry No. 7 under Members of Parliament in this Ministry's Resolution No. EL-II-1(7)/65, dated the 12th February, 1968 constituting the Central Electricity Consultative Council shall be substituted by the following entry:—

"7. Shri G. Y. Krishnan, Member of Parliament (Lok Sabha).

#### ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Members concerned, the State Governments, the State Electricity Boards, the Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

The March 1969

No. EL. II-12(21)/61-Vol.III.—In this Ministry's Resolution No. EL.II-12(21)/61, dated the 26th September, 1962, relating to the constitution of the Delhi Thermal Project control Board for the installation of three sets of 50/62.5 MW each at Delhi as amended from time to time, for existing entries (13) under paragraph 2 and XI under paragraph 6, the following entries shall be substituted:—

Paragraph 2:

(13) Secretary (Local Self Government and P.W.D.), Delhi Administration. *Member*

Paragraph 6:

(XI) Secretary (Local Self Government and P.W.D.), Delhi Administration. *Member*

#### ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to the Governments of Punjab and Haryana, The Delhi Administration, The Delhi Municipal Corporation, The Haryana State Electricity Board, The Ministries Department of the Government of India, The Prime Minister's Secretariat, The Secretary to the President, The Planning Commission and The Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

K. P. MATHRANI, Secy.

New Delhi, the 20th March 1969

#### RESOLUTION

No. 22/7/66-DW.I.—In paragraph 2 of this Ministry's Resolution No. 22/7/66-DW.I, dated the 10th December, 1968, the existing entry against Serial No. 2 under the 'Committee of Chief Ministers' may be substituted as follows:—

"2. Chief Minister, Punjab or his representative."

#### ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated for information to the State Governments of Rajasthan, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and to the Ministries of Finance, Home Affairs and Food, Agriculture, Community Development and Co-operation and the Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments concerned be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

O. P. CHADHA, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 20th March 1969

No. 24/3/68-FP.—In pursuance of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Information and

Broadcasting No. 1/29/58-FP, dated the 5th February, 1959, as amended from time to time, the Central Government has nominated Shri H. R. Mahajani, Member, Advisory Panel of the Central Board of Film Censors at Bombay, as a member of the Film Advisory Board, Bombay, *vice* Shri Lalit Kumar Khatau, till further orders.

2. The Central Government has also nominated Dr. D. K. Rangnekar as a member of the Film Advisory Board, Bombay, *vice* Shri G. S. Poddar, for a term of two years.

BANU RAM AGGARWAL, Under Secy.

**MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION**

**Department of Labour & Employment**

*New Delhi, the 18th March 1969*

**RESOLUTION**

No. 43/2/68-L&E(L).—In the Government of India Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Depart-

ment of Labour and Employment) Resolution No. 36/14/66-L&E, dated December 24, 1966 published in the Gazette of India Part I, Section 1, dated January 7, 1967, Dr. B. N. Ganguli was appointed as a member of the National Commission on Labour. Consequent on his resignation, Dr. Ganguli ceased to be a member of the Commission from March 3, 1969.

**ORDER**

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India/State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

P. M. NAYAK, Additional Secy.

